भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 901
दिनांक 29.11.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

विकसित भारत 2047 को प्राप्त करने का मिशन

901. श्री इटेला राजेंदरः
श्रीमती डी. के. अरुणाः
श्री सुरेश कुमार शेटकरः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भारत के प्रधानमंत्री की विभिन्न देशों की यात्राओं के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान परियोजना-वार और देश-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) ऐसे समझौता ज्ञापनों से देश को और विभिन्न क्षेत्रों को क्या लाभ प्राप्त हुए/होने की संभावना है; और

(घ) उक्त परियोजनाओं के अंतर्गत पहचाने गए और शामिल किए गए क्षेत्र क्या हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री पबित्र मार्गेरिटा]

(क) से (घ) उच्च स्तरीय यात्राएँ विदेशों में भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित करने, बाज़ार पहुँच का विस्तार करने और आर्थिक साझेदारी के लिए आधार बनाने का एक स्थापित साधन है। ऐसा विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के देशों के साथ है। प्रधानमंत्री की हाल की विदेश यात्राओं के दौरान विकास कार्यों के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के कार्यान्वयन की स्थिति अनुबंध-I पर दी गई है। घरेलू विकास परियोजनाओं के संबंध में विदेशी भागीदारों के साथ भी करार और समझौता ज्ञापन पर

हस्ताक्षर किए गए हैं। ऐसे समझौता ज्ञापनों की एक व्याख्यात्मक सूची अनुबंध-II पर दी गई है। एक साथ मिलकर, ये प्रयास 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने की खोज को गति देने में योगदान देते हैं।

*****

अनुबंध -I

विदेशों में विकासात्मक कार्य/परियोजनाएं

क्र. सं.	देश	विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं हेतु समझौता ज्ञापन	विवरण एवं वर्तमान स्थिति	देश को हुए/होने वाले संभावित लाभ	पहचाने गए क्षेत्र और सेक्टर
1	बांग्लादेश	बांग्लादेश-भारत डिजिटल सेवा और रोजगार प्रशिक्षण (बीडीएसईटी) केंद्र के लिए आईसीटी उपकरण, पाठ्यक्रम और संदर्भ पुस्तकों की आपूर्ति और प्रशिक्षण पर समझौता ज्ञापन;	मार्च 2021 में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान परियोजना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। वर्तमान भौतिक और वित्तीय प्रगति क्रमशः 80% और 75% है।	आईटी प्रयोगशालाएं और अन्य अवसंरचना/केंद्र स्थानीय स्तर पर कुशल मानव संसाधनों का एक पूल निर्मित करने के लिए बांग्लादेश सरकार को सहायता प्रदान करेंगे।	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी।
2	बांग्लादेश	पांच पैकेजों (अमीन बाजार - कलियाकोईर, रूपपुर - ढाका, रूपपुर - गोपालगंज, रूपपुर - धमराई, रूपपुर - बोगरा) की रूपपुर विद्युत निकासी परियोजना की नींव रखी।	2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। (दो पैकेज पूरे हो चुके हैं)	बांग्लादेश की ऊर्जा आवश्यकताओं में योगदान देना तथा ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना।	ऊर्जा और पारेषण
3	बांग्लादेश	कुठीबाड़ी में रवींद्र भवन सुविधाओं का उद्घाटन	जून 2023 में पूरा किया गया।	साझा सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार	कला एवं संस्कृति
4	लाओ पीडीआर	लुआंग प्रबांग प्रांत में फलक-	इन तीन क्यूआईपी को मेकांग	क्यूआईपी से स्थानीय समुदायों	क्यूआईपी लाओ रामायण की

		फलम (लाओ रामायण) नाटक की प्रदर्शन कला की विरासत के संरक्षण पर क्यूआईपी लुआंग प्रबांग प्रांत में वाट फाकिया मंदिर के जीर्णोद्धार पर क्यूआईपी चम्पासक प्रांत में छाया कठपुतली थियेटर के प्रदर्शन के संरक्षण पर क्यूआईपी	गंगा सहयोग (एमजीसी) तंत्र के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है और 10 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री की वियनतियाने यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। इन क्यूआईपी का कार्यान्वयन चल रहा है।	को सीधे लाभ मिलता है, जिसके परिणाम तत्काल और प्रत्यक्ष होते हैं, जो आर्थिक और सामाजिक विकास तथा जन कल्याण में सुधार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये जमीनी परियोजनाएँ, जो ज्यादातर दूरदराज के इलाकों में हैं, बहुत अधिक सद्भावना पैदा कर रही हैं। ये क्यूआईपी भारत और लाओ पीडीआर की साझा सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत के संरक्षण पर केंद्रित हैं।	विरासत के संरक्षण, रामायण से संबंधित भितिचित्रों के साथ वाट पकेया बौद्ध मंदिर के जीर्णोद्धार, तथा चम्पासक प्रांत में रामायण पर आधारित छाया कठपुतली थियेटर को समर्थन देने से संबंधित हैं।
5	नेपाल	एसजेवीएन लिमिटेड और नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) के बीच अरुण 4 परियोजना के विकास और कार्यान्वयन के लिए करार	एसजेवीएन द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है तथा अब एनईए और एसजेवीएन के बीच इस परियोजना के डिजाइन मापदंडों पर बातचीत चल रही है।	एनईए और एसजेवीएन का संयुक्त उद्यम (कम से कम 51% हिस्सेदारी के साथ) 490 मेगावाट की अरुण 4 परियोजना का विकास करेगा। अरुण 4 परियोजना के विकास से ऊर्जा सहयोग मजबूत होगा, नेपाल के बिजली उत्पादन में	जल विद्युत

				वृद्धि होगी, स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच आसान होगी और दोनों देशों के बीच आर्थिक एकीकरण बढ़ेगा।	
6	त्रिनिदाद और टोबैगो	भारत और कैरिकॉम शिखर सम्मेलन (21-22 नवंबर, 2024) के लिए प्रधानमंत्री की गुयाना यात्रा के दौरान त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ एसएमई पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होने के बाद, वर्तमान में बोली प्रबंधन प्रक्रिया जारी है, मशीनरी जनवरी 2025 तक भेज दी जाने की संभावना है।	इससे त्रिनिदाद और टोबैगो में एसएमई क्षेत्र को मजबूत करने, स्थानीय रोजगार सृजित करने तथा निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।	एसएमई - लघु एवं मध्यम उद्यम (कृषि - खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र)
7	गुयाना	प्रधानमंत्री की इसी यात्रा के दौरान गुयाना के साथ यूपीआई पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।	वाणिज्यिक समझौते को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए गुयाना के साथ बातचीत जारी है।	इससे अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने में मदद मिलेगी, तथा बी2बी (बिजनेस टू बिजनेस), पी2पी (पीपुल टू पीपल) और जी2पी (गवर्नमेंट टू पीपल) लेन-देन को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी।	डिजिटल अर्थव्यवस्था
8	यूक्रेन	प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यूक्रेन यात्रा के दौरान 23.08.2024 को भारत और	यह समझौता ज्ञापन चालू है और पांच साल अर्थात 22.08.2029 तक वैध है।	मानवीय सहायता प्रदान करने की भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप एचआईसीडीपी पर	समझौता ज्ञापन में सामाजिक-आर्थिक विकास, आजीविका सहायता, महिला

		यूक्रेन के बीच उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं (एचआईसीडीपी) के कार्यान्वयन के लिए मानवीय अनुदान सहायता पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।	इस समझौता ज्ञापन के तहत 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की परियोजनाओं को पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा। अगले चरण में यूक्रेन सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं के लिए परियोजना-विशिष्ट समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना शामिल होगा।	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए । चूंकि ये परियोजनाएं भारतीय कंपनियों की भागीदारी से क्रियान्वित की जाती हैं, इसलिए ऐसी परियोजनाएं लाभार्थी देशों में भारतीय कंपनियों को भी अवसर प्रदान करती हैं ।	सशक्तिकरण एवं बाल कल्याण तथा शिक्षा, स्वास्थ्य प्रशिक्षण , कृषि एवं कृषि उद्योग, सूक्ष्म सिंचाई, नवीकरणीय ऊर्जा, व्यापार, परिवहन और संचार के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में अवसंरचना निर्माण के माध्यम से सामुदायिक जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए मानवीय अनुदान सहायता प्रदान की गई है, जिन पर पारस्परिक सहमति हो सकती है।
9	वियतनाम	भारत-वियतनाम नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान- 21 दिसंबर 2020, भारतीय दूतावास, हनोई और दूरसंचार विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय, वियतनाम के बीच राष्ट्रीय दूरसंचार विश्वविद्यालय, न्हा ट्रांग,	कार्यान्वित	आईटी, डेटा रिसेप्शन आदि में वियतनाम की क्षमता निर्माण को बढ़ाकर द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करना	रक्षा क्षेत्र

		वियतनाम में आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारतीय अनुदान सहायता के लिए समझौता, सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के क्षेत्र में प्रशिक्षण और सेवाओं के प्रावधान के साथ, दूरसंचार विश्वविद्यालय, न्हा ट्रांग में आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क में आईटी अवसंरचना की स्थापना की सुविधा के लिए।			
10	जर्मनी	6वें आईजीसी के दौरान प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान विकास परियोजनाओं पर समझौता ज्ञापन/जेडीआई	त्रिकोणीय विकास सहयोग पर संयुक्त विकास बैठक वर्तमान स्थिति: सक्रिय	तीसरे देशों में सतत विकास परियोजनाओं पर सहयोग	हरित एवं टिकाऊ विकास
11	संयुक्त अरब अमीरात	अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली परिसर की स्थापना पर समझौता ज्ञापन (जुलाई 2023)	कैंपस की स्थापना की गई। बीटेक और एमटेक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं	भारतीय शैक्षणिक संस्थानों का अंतर्राष्ट्रीयकरण। यूएई में भारतीय समुदाय के लिए अधिक शैक्षिक अवसर	शिक्षा
12	संयुक्त अरब अमीरात	भारत मार्ट (फरवरी 2024)	विचार-विमर्श के अंतर्गत/कार्यान्वयन के	एसएमई सहित भारतीय निर्यात के लिए अधिक बाजार	व्यापार

			विभिन्न चरणों में	पहुंच	
13	संयुक्त अरब अमीरात	भारत-मध्य पूर्व- यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईईसी) पर अंतर-सरकारी रूपरेखा समझौता (फरवरी 2024)	भारत-यूएई के बीच वर्चुअल व्यापार गलियारे का उद्घाटन	व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना, व्यापार करने में आसानी और व्यापार में लागत और समय को कम करना	रसद

<u>**अनुबंध- II**</u>

भारत में विकासात्मक गतिविधियाँ/परियोजनाएँ

क्र. सं.	देश	सरकार द्वारा 01.07.2019 से प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन	विवरण एवं वर्तमान स्थिति	देश को हो रहे/संभावित लाभ	उक्त परियोजना के अंतर्गत पहचाने गए और शामिल किए गए क्षेत्र और सेक्टर
1	जर्मनी	6 वें आईजीसी के दौरान प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान विकास परियोजनाओं पर समझौता ज्ञापन /जेडीआई	पर्यावरण अनुकूल एवं सतत विकास के लिए साझेदारी पर जेडीआई वर्तमान स्थिति: लागू है	भारत में सतत विकास परियोजनाओं के लिए जर्मनी द्वारा वित्तीय और तकनीकी सहायता	नवीकरणीय ऊर्जा, स्थायी शहरी विकास, पर्यावरण अनुकूल गतिशीलता, स्थायी कृषि, आदि
			नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी के संबंध में भारत-जर्मनी विकास सहयोग पर संयुक्त शोध बैठक वर्तमान स्थिति: लागू है	भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए जर्मनी द्वारा वित्तीय और तकनीकी सहायता	नवीकरणीय ऊर्जा
			भारत-जर्मनी ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर जेडीआई	भारत में हरित हाइड्रोजन उद्योग के विकास के लिए सहयोग	हरित हाइड्रोजन

			वर्तमान स्थिति: लागू है		
			कृषि पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन पर जेडीआई (लाइटहाउस इनिशिएटिव) वर्तमान स्थिति: लागू है	पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन और कृषि -खाद्य प्रणालियों के संबंध में सहयोग	कृषि पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
			वन परिदृश्य पुनरुद्धार के क्षेत्र में सहयोग पर संयुक्त शोध परियोजना वर्तमान स्थिति: लागू है	वन संरक्षण एवं पुनरुद्धार, जलवायु संरक्षण और जैव विविधता के संरक्षण के संबंध में सहयोग	वन एवं पर्यावरण, जैव विविधता
2	फ्रांस	22 अगस्त 2019 और 14 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन	राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई), नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार और फ्रांसीसी वैकल्पिक ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा आयोग (सीईए) के बीच समझौता ज्ञापन	हाइड्रोजन ऊर्जा और ईंधन सैल के क्षेत्रों में सहयोग	नवीकरणीय ऊर्जा
			नए राष्ट्रीय संग्रहालय और संग्रहालय विज्ञान पर सहयोग पर आशय पत्र: लागू है (आशय पत्र को आगे बढ़ाने के लिए कार्य के विस्तृत दायरे को शामिल करते हुए एक और समझौता ज्ञापन पर काम किया जा रहा है)	भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय के विकास पर ज्ञान और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान	सांस्कृतिक सहयोग
			डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में	चुनौतियों का समाधान करने के लिए	डिजिटल प्रौद्योगिकी

			सहयोग पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और फ्रांस के अर्थव्यवस्था मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन	डिजिटल प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने का समर्थन करता है	
			इन्वेस्ट इंडिया और बिजनेस फ्रांस के बीच समझौता ज्ञापन	निवेश को बढ़ावा देना भारत और फ्रांस के स्टार्टअप्स के बीच सुविधा और सहयोग।	स्टार्टअप और नवाचार
			भारत-फ्रांस संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन तृष्णा कार्यान्वयन व्यवस्था	तृष्णा को उच्च-रिज़ॉल्यूशन थर्मल इन्फ्रारेड इमेजरी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो जल संसाधनों, भूमि सतह के तापमान और वनस्पति स्वास्थ्य की निगरानी जैसे अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण है।	अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जल संसाधन, भूमि प्रबंधन और वन।
			स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और फ्रांस के बीच आशय पत्र	इससे दोनों देशों के लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में सुधार होगा	स्वास्थ्य
3	सिंगापुर	शिक्षा सहयोग और कौशल विकास पर समझौता ज्ञापन	02 सितंबर, 2024 को हस्ताक्षरित	क्षमता और कौशल विकास पर सहयोग बढ़ाना उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना	तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण शिक्षण संस्थान

				सूचना और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना शिक्षण स्टाफ, शैक्षिक प्रशासकों और छात्रों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना शिक्षक प्रशिक्षण पर सहयोग को बढ़ावा देना	
4	यूएसए	प्रधानमंत्री की 21 से 28 सितंबर 2019 तक अमेरिका यात्रा के दौरान ऊर्जा सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए भारतीय कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड और अमेरिकी कंपनी टेल्यूरियन इंक के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।		ऊर्जा सहयोग को मजबूत करना	ऊर्जा क्षेत्र
5	यूएसए	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा	28.09.2021 को हस्ताक्षरित	समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्वास्थ्य	स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र

		अमेरिकी स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग के बीच स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सहयोग और साझेदारी बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन।		सुरक्षा एवं संरक्षा में अनुसंधान, संचारी और गैर-संचारी रोगों की रोकथाम, निदान, उपचार और नियंत्रण, स्वास्थ्य प्रणाली और स्वास्थ्य नीति में सहयोग और नवाचार को प्रोत्साहित करना है।	
6	यूएसए	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और अमेरिका के राष्ट्रीय एलर्जी एवं संक्रामक रोग संस्थान के बीच अत्यधिक उत्पादक भारत-अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र (आईसीईआर) कार्यक्रम के लिए संयुक्त समर्थन जारी रखने हेतु समझौता ज्ञापन- यह एक संक्रामक रोग अनुसंधान साझेदारी है जो चेन्नई में राष्ट्रीय क्षय रोग अनुसंधान संस्थान में केंद्रित है।	24.09.2024 को हस्ताक्षरित	इस समझौता ज्ञापन ("एमओयू") के तहत किए जाने वाले सहयोग में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं, परंतु यह इन तक ही सीमित नहीं है: सहयोगी अनुसंधान परियोजनाएं; वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का आदान-प्रदान; वैज्ञानिक बैठकें, कार्यशालाएं और संगोष्ठियां; प्रशिक्षण गतिविधियां और परामर्श; संयुक्त अनुसंधान करने के लिए वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का दीर्घकालिक कार्य; नैदानिक अनुसंधान अवसंरचना, डेटा और सूचना प्रबंधन प्रणाली, और नमूना भंडार सहित जैव चिकित्सा/संक्रामक रोग अनुसंधान क्षमता का संवर्धन और सुदृढ़ीकरण;	स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र

				अनुसंधान सामग्री, डेटा, प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक प्रकाशनों का आदान-प्रदान; आपसी सहमति से पहचाने गए सहयोग के अन्य रूप ।	
7	यूएसए	भारत और अमेरिका के बीच वैश्विक विकास के लिए त्रिकोणीय सहयोग (एसजीपी) पर मार्गदर्शक सिद्धांतों के वक्तव्य को पांच साल के लिए बढ़ाने पर समझौता ज्ञापन	एसजीपी समझौते की वैधता 2026 तक बढ़ाई गई	यह समझौता दोनों देशों की एक साथ मिलकर काम करने और मांग-संचालित विकास साझेदारी प्रदान करने के लिए अपनी संयुक्त क्षमताओं का लाभ उठाने की संयुक्त प्रतिबद्धता को पूरा करने में मदद करता है। अमेरिका के साथ यह त्रिकोणीय सहयोग वैश्विक स्तर पर देशों के साथ भारत की अन्य चल रही और भविष्य की विकास साझेदारियों, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता का पूरक होगा।	
8	यूएसए	भारत ने 21 जून 2023 को वाशिंगटन डी.सी. में आर्टेमिस समझौते - शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए चंद्रमा, मंगल, धूमकेतु और क्षुद्रग्रहों के नागरिक		नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण और उपयोग के क्षेत्र में सहयोग।	अंतरिक्ष

		अन्वेषण और उपयोग में सहयोग के सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किए।			
9	यूएसए	भारत ने पिलर III (स्वच्छ अर्थव्यवस्था), पिलर IV (निष्पक्ष अर्थव्यवस्था) और व्यापक समझौते के तहत इंडो-पैसिफिक आर्थिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ) समझौतों पर हस्ताक्षर किए।	21 सितंबर 2024 को हस्ताक्षरित	यह समझौता स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विकास, पहुंच और उपयोग को सुगम बनाएगा, निवेश को बढ़ावा देगा, भ्रष्टाचार विरोधी उपायों, कर पारदर्शिता आदि को मजबूत करेगा तथा कारोबारी माहौल में सुधार करेगा।	स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकी आदि।
10	यूएसए	प्रधानमंत्री की 21 से 23 सितंबर 2024 तक की यात्रा के दौरान भारत-अमेरिका औषधि नीति ढांचे से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए		यह सिंथेटिक दवाओं और पूर्ववर्ती रसायनों के अवैध उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय तस्करी को रोकने के लिए सहयोग को गहरा करेगा और समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य साझेदारी को प्रगाढ़ करेगा।	स्वास्थ्य देखभाल
11	मालदीव	समुद्र मार्ग से यात्री और कार्गो सेवाओं के लिए समझौता ज्ञापन	जारी	दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों और लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ाना। भारत और मालदीव के बंदरगाहों के बीच सीधे माल की	आवाजाही, अर्थव्यवस्था एवं व्यापार तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क

				आवाजाही की सुविधा के लिए भारत मालदीव शिपिंग सेवा का संचालन करना	
12	श्रीलंका	डिजिटल भुगतान के लिए एनपीसीएल इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और लंकापे के बीच समझौता ज्ञापन।	श्रीलंका मेंयूपीआई क्यूआर आधारित भुगतान प्रणाली को 12 फरवरी, 2024 को प्रधानमंत्री और श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे द्वारा वर्चुअल रूप से शुरू किया गया था।	यूपीआई प्रणाली की शुरूआत से श्रीलंका आने वाले भारतीय पर्यटकों को भुगतान और लेनदेन में आसानी हो रही है।	डिजिटल कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देना।
13	श्रीलंका	नागापट्टिनम (तमिलनाडु) और श्रीलंका के जाफना में कांकेसंथुराई (केकेएस) बंदरगाह के बीच यात्री नौका सेवा शुरू करने की घोषणा ।	नागपट्टिनम (तमिलनाडु) और कांकेसंथुराई (केकेएस) के बीच यात्री नौका सेवा अक्टूबर 2023 में शुरू की गई थी। इसके बाद पोत परिवहन, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने नौकायन के लिए एक वाणिज्यिक ऑपरेटर की पहचान की है, जिसने 16 अगस्त 2024 से परिचालन शुरू कर दिया है।	भारत और श्रीलंका के बीच लोगों के बीच आपसी संपर्क, व्यापार, पर्यटन और समुद्री संपर्क को सुविधाजनक बनाना।	
14	मॉरीशस	मॉरीशस के अगलेगा द्वीप पर समुद्री और हवाई परिवहन सुविधाओं में	भारत के प्रधानमंत्री और मॉरीशस के पूर्व प्रधानमंत्री ने 29 फरवरी 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के	इस समझौता ज्ञापन के तहत निर्मित रनवे और जेटी ने मॉरीशस और अगालेगा के बीच समुद्री और हवाई	

		सुधार के लिए समझौता ज्ञापन	माध्यम से इस समझौता ज्ञापन के तहत निर्मित रनवे और जेटी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया।	संपर्क को बढ़ाया है । यह बुनियादी ढांचा मॉरीशस सरकार को अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) की निगरानी में भी मदद कर रहा है।	
15	बांग्लादेश	चिलाहाटी-हल्दीबाड़ी रेल संपर्क के माध्यम से ढाका-न्यू जलपाईगुड़ी-ढाका मार्ग पर यात्री ट्रेन सेवा	साप्ताहिक सेवा रूप से परिचालन (वर्तमान में, सुरक्षा स्थिति के कारण इसे अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है)	लोगों के बीच आपसी संबंध बढ़ाना तथा पर्यटन को बढ़ावा देना।	रेल संपर्क
16	बांग्लादेश	3 सीमा हाटों का उद्घाटन - नलिकाता (भारत) - सईदाबाद (बांग्लादेश); रिंग्कु (भारत) - बागान बाड़ी (बांग्लादेश) और भोलागंज (भारत) - भोलागंज (बांग्लादेश)	उदघाटन के बाद परिचालन शुरू कर दिया जाएगा (फिलहाल सुरक्षा स्थिति के कारण इसे अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है)	सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आजीविका में योगदान देना तथा लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाना।	सीमा संपर्क और व्यापार।
17	सऊदी अरब	सऊदी ऊर्जा मंत्रालय और भारत के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के	विचाराधीन/कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में	ऊर्जा विविधीकरण और आत्मनिर्भरता	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा

		संबंध में समझौता ज्ञापन (अक्टूबर 2019)			
18	सऊदी अरब	सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ मिलिट्री इंडस्ट्रीज (जीएएमआई) और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन (अक्टूबर 2019)	विचाराधीन/कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में	मेक इन इंडिया, रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता और संभावित रक्षा निर्यात	रक्षा एवं सुरक्षा
19	सऊदी अरब	चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग के लिए केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और सऊदी खाद्य एवं औषध प्राधिकरण (एसएफडीए) के बीच समझौता ज्ञापन (अक्टूबर 2019)	विचाराधीन/कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में	चिकित्सा उपकरणों और फार्मास्यूटिकल्स का निर्यात	स्वास्थ्य, चिकित्सा और फार्मास्यूटिकल्स
20	सऊदी अरब	सऊदी अधिराज्य के लघु और मध्यम उधम सामान्य प्राधिकरण	विचाराधीन/कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में	मेक इन इंडिया, लघु एवं मध्यम उद्यमों को मजबूत बनाना	एसएमई क्षेत्र

		(मोनशात) और भारत गणराज्य के अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम), नीति आयोग के बीच आशय पत्र (अक्टूबर 2019)			
21	सऊदी अरब	भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल) और सऊदी अरामको के बीच समझौता ज्ञापन। (अक्टूबर 2019)	विचाराधीन/कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में	ऊर्जा आत्मनिर्भरता	ऊर्जा क्षेत्र
22	सऊदी अरब	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) और सऊदी पेमेंट्स के बीच समझौता ज्ञापन (अक्टूबर 2019)	विचाराधीन/कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में	डिजिटलीकरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सरलता, मुद्रा परिवर्तन शुल्क की बचत	वाणिज्य एवं निवेश
23	संयुक्त अरब अमीरात	भारत और यूएई के बीच सीमा पार लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं (आईएनआर-एईडी) के उपयोग को बढ़ावा देने के	विचाराधीन/कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में	व्यापार को बढ़ावा देना	वित्त

		लिए एक ढांचे की स्थापना के संबंध में समझौता ज्ञापन (जुलाई 2023)			
24	संयुक्त अरब अमीरात	भारत और यूएई के बीच भुगतान और संदेश प्रणालियों को आपस में जोड़ने के संबंध में समझौता ज्ञापन (जुलाई 2023) त्वरित भुगतान प्लेटफॉर्म-यूपीआई (भारत) और एएएनआई (यूएई) को आपस में जोड़ने के लिए करार (फरवरी 2024) घरेलू डेबिट/क्रेडिट कार्डों को आपस में जोड़ने के लिएकरार- रुपे (भारत) और जेएवाईडबल्यूएएन (यूएई) (फरवरी 2024)	विचाराधीन/कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में	सीमा पार लेनदेन में सरलता और लेनदेन लागत में कटौती	वित्त
25	संयुक्त अरब अमीरात	राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएमएचसी),	विचाराधीन/कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में	समुद्री अनुसंधान, संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	संस्कृति

		लोथल, गुजरात के साथ सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (फरवरी 2024)			
26	संयुक्त अरब अमीरात	डिजिटल अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (फरवरी 2024)	विचाराधीन/कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में	डिजिटल अवसंरचना तंत्र को मजबूत बनाना और उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बनाना	उन्नत प्रौद्योगिकी
27	संयुक्त अरब अमीरात	विद्युत अंतर्संबंध और व्यापार के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन (फरवरी 2024)	विचाराधीन/कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में	ऊर्जा व्यापार और ऊर्जा आत्मनिर्भरता में वृद्धि	विद्युत

*****